



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 2430 /2026

सतवीर

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी

आवेदक अधिवक्ता

: अनुपम दुबे

प्रतिवादी अधिवक्ता

: जी.ए., गणेश शंकर श्रीवास्तव, रवि शंकर कनौजिया

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. लिस्ट में बदलाव किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री अनुपम दुबे की मदद से सीनियर अधिवक्ता श्री गौरव कक्कड़ साथ ही राज्य के लिए ए.जी.ए. श्री सुनील कुमार को सुना और रिकॉर्ड देखा।
3. आवेदक मुकदमा अपराध संख्या 194/2025, धारा 103(1), 115(2), 61(2) बीएनएस, पुलिस स्टेशन कासना, जिला गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत, विचारण लंबित रहने के दौरान जमानत चाहता है।
4. आवेदक के अधिवक्ता ने कहा है कि इसी तरह के सह-अभियुक्त, रोहित को इस न्यायालय ने 5.1.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 45317/2025 में पास किए गए आदेश के ज़रिए पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया है। आवेदक 25.8.2025 से जेल में बंद हैं, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक का रोल सह-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अभियुक्त जैसा ही है, जिन्हें पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वे भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने के हकदार हैं।

5. जमानत की अर्जी का विद्वान ए.जी.ए. ने जोरदार विरोध किया है। हालाँकि, सह- अभियुक्त के समानता होने और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास न होने की ऊपर बताई गई असल बातों पर उन्होंने कोई सवाल नहीं उठाया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पार्टियों के अधिवक्ताओं की दलीलें, रिकॉर्ड में मौजूद सबूत, और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीओआर/22410/2021 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि.एल.जे. 93 के मामले में इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, साथ ही सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो अन्य और 2022 एससीसी ऑनलाइन एससी 825 में रिपोर्ट किए गए दूसरे मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को भी ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, न्यायालय का मानना है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत के लिए मामला बनाया है। समानता के आधार पर जमानत अर्जी मंजूर की जाती है।

7. आवेदक- सतवीर जो ऊपर बताए गए आपराधिक मामले में शामिल हैं, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बॉन्ड और उतनी ही रकम के दो जमानतदार देने पर इन शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों को सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक जमानत के दौरान सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक सरकारी गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराया-धमकाएगा।

(iii) आवेदक तय तारीख पर विचारण न्यायालय के सामने पेश होगा।

8. ऊपर दी गई किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, प्रॉसिक्यूशन को इस न्यायालय में जमानत रद्दीकरण आवेदन देने की आज़ादी होगी।

9. बॉन्ड स्वीकार करने से पहले, आवेदक और जमानतदार की पहचान, स्थिति और रहने का सबूत संबंधित न्यायालय से सत्यापित किया जाएगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



10. यह साफ़ किया जाता है कि आवेदक को ज़मानत देते समय की गई बातें, गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी अलग राय बनाने में विद्वान विचारण न्यायाधीश पर किसी भी तरह से असर नहीं डालेंगी।

(माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

27 जनवरी, 2026

(विकास वर्मा)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।